देश की ज़िद
कोरोना को हराना है

डेमोक्रेटिक फ्रंट

पंचकुला हरियाणा से प्रकाशित

लोकतंत्र की आवाज

दिनाक : 16 जनवरी से 31 जनवरी 2022, अंक-3, वर्ष-1

Email : democraticfront2021@gmail.com | democraticfront.com | RNI: HARMIN11362 | मूल्य : 2 रुपये

देश की ज़िद
कोरोना को हराना है

एक नज़र

कोरियाई बैंड 'टूमोरो एक्स टुगेदर' मार्च में दर्शकों के बीच देगा प्रस्तुति

नई दिल्ली/(एजेंसी)। मशहूर दक्षिण कोरियाई बैंड 'टूमोरो एक्स टुगेदर' पांच और छह मार्च को तीसरी बार दर्शकों के बीच प्रस्तुति देगा। उनकी प्रबंधन एजेंसी 'बिग हिट म्यूजिक' ने यह जानकारी दी। बैंड के फैन ग्रुप 'मोमेंट ऑफ ऑलवेजनेस' (एमओए) के लिए किए जा रहे दो दिवसीय कार्यक्रम का नाम 'एमओए एक्स टुगेदर' है। इस कार्यक्रम में बैंड के सदस्य सोबिन, योनजुन, बेओमग्यू, ताएह्युन और ह्यूनिंगकाई प्रस्तुति देंगे। इसे सोशल मीडिया पर लाइव भी दिखाया जाएगा। एजेंसी के अनुसार, छह मार्च को कार्यक्रम के वैश्विक संस्करण के दौरान बैंड के विदेशी भाषा के गीतों पर भी प्रस्तुति होगी।

प्रधानमंत्री ने विख्यात कार्टूनिस्ट नारायण देबनाथ के निधन पर जताया शोक

नई दिल्ली/(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को विख्यात कार्टूनिस्ट नारायण देबनाथ के निधन पर शोक व्यक्त करते हुये कहा कि उन्होंने अपनी कृतियों, कार्टूनों और दृष्टांतों के माध्यम से अनेक लोगों के जीवन को रोशन किया। 97 वर्षीय देबनाथ का आज कोलकात में निधन हो गया। उन्हें पिछले साल पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, ष्श्री नारायण देबनाथ जी ने अपनी कृतियों, कार्टूनों और दृष्टांतों के माध्यम से अनेक लोगों के जीवन को रोशन किया। उनकी रचनाएं उनकी बौद्धिक शक्ति को दर्शाती हैं। उनके द्वारा बनाए गए पात्र हमेशा लोकप्रिय रहेंगे। उनके निधन से आहत हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।

सरकार की सदबुद्धि के लिए एनएसयूआई ने किया यज्ञ, ऑनलाईन परीक्षा की उठाई मांग

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में कॉलेजों में ऑफलाइन परीक्षाएं कराने का विरोध तेज हो गया है। भोपाल में एनएसयूआई और छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में 'सद्बुद्धि यज्ञ' किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यज्ञ कर सरकार के सद्बुद्धि के लिए कामना की। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के निजी सचिव विजय बुधवानी द्वारा छात्रों को चांटा मारने और बदतमीजी पर 24 घंटे में छात्रों से माफी मांगने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर माफी नहीं मांगी तो मंत्री मोहन यादव के बंगले का घेराव करेंगे। एनएसयूआई के मेडिकल विंग के प्रदेश समन्वयक रवि परमार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन सात हजार से अधिक मरीज मिल रहे हैं। इसके बाद भी सरकार ऑफलाइन परीक्षा कराने पर डटी हुई है। सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हमने 'सद्बुद्धि यज्ञ' किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हम कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने की मांग करते हैं।

अलीगढ़ में नहीं होगी धर्म संसद, प्रशासन ने अनुमति देने से किया इनकार

अलीगढ़। हरिद्वार विवाद के बाद अलीगढ़ जिला प्रशासन ने 22 व 23 जनवरी को शहर में प्रस्तावित धर्म संसद की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। कई प्रतिष्ठित नागरिकों, अल्पसंख्यक संगठनों और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने भी जिला प्रशासन को एक पत्र लिखकर इस आयोजन की अनुमति देने से इनकार करने की मांग की थी। उनका कहना था कि यह आयोजन सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर में तनाव पैदा कर सकता है। एडीएम (नगर) आरके पटेल ने कहा कि चूंकि राज्य में आदर्श आचार संहिता और कोविड दिशा-निर्देश लागू हैं, इसलिए आयोजक को अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा, न तो अनुमति दी गई थी और न ही दी जाएगी।
कई वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, प्रोफेसरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी को पत्र लिखकर कहा था कि, अलीगढ़ में धर्म संसद का आयोजन हरिद्वार की तर्ज पर किया जा रहा है। चूंकि अलीगढ़ एक संवेदनशील शहर है, इसलिए यह आयोजन बाधित हो सकता है। पूरे देश का शांतिपूर्ण माहौल विधानसभा चुनावों के बीच समाज में तनाव और भय पैदा कर सकता है। इसलिए जनहित में इस तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

रक्षा मंत्री ने दिया स्पष्टीकरण

इस साल क्यों तमिलनाडु की झांकी परेड में नहीं होगी शामिल

नई दिल्ली, गणतंत्र दिवस परेड में तमिलनाडु की झांकी नहीं शामिल किए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नाराजगी जाहिर की है। सोमवार को पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु की झांकी परेड में शामिल नहीं होने से राज्य के लोगों की भावनाएं आहत होंगी। साथ ही उनकी देशभक्ति की भावनाओं को गहरा ठेस पहुंचेगी। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग रखी थी।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया स्पष्टीकरण
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र का जवाब देते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ समिति की बैठकों के पहले तीन दौर में तमिलनाडु की झांकी को शामिल किया गया था। लेकिन वर्ष 2022 की गणतंत्र दिवस परेड के लिए चुनी गई 12 झांकियों की अंतिम सूची में जगह नहीं बना सकी। साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि ष्रक्षा मंत्रालय सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों से झांकियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त झांकी के प्रस्ताव / कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, नृत्यकला आदि के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों की विशेषज्ञ समिति की बैठकों की एक श्रृंखला में विभागों का मूल्यांकन किया जाता है।

- गणतंत्र दिवस परेड में तमिलनाडु की झांकी नहीं शामिल होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नाराजगी जाहिर की है। सोमवार को पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु की झांकी परेड में शामिल नहीं होने से राज्य के लोगों की भावनाएं आहत होंगी
- गणतंत्र दिवस परेड में तमिलनाडु की झांकी नहीं शामिल किए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नाराजगी जाहिर की है।
- सोमवार को पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु की झांकी परेड में शामिल नहीं होने से राज्य के लोगों की भावनाएं आहत होंगी। साथ ही उनकी देशभक्ति की भावनाओं को गहरा ठेस पहुंचेगी।
- उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग रखी थी।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री को लिखे पत्र का जवाब देते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में अपना पक्ष रखा है।

विशेषज्ञ समिति विषय, अवधारणा, डिजाइन और के आधार पर प्रस्तावों की जांच करती है।
विशेषज्ञ समिति द्वारा होती है झांकियों की शार्टलिस्टिंग
पत्र में आगे रक्षा मंत्री ने लिखा कि परेड की समग्र अवधि में झांकियों के लिए आवंटित समय स्लाट के अनुसार, विशेषज्ञ समिति द्वारा झांकियों की शार्टलिस्टिंग की जाती है। गणतंत्र दिवस परेड -2022 के लिए, तमिलनाडु राज्य के प्रस्ताव सहित राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से कुल 29 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तमिलनाडु की झांकी पर पहले तीन दौर की बैठकों में शामिल की गई थी। लेकिन तीसरे दौर की बैठक के बाद झांकी चुनी गई 12 झांकियों की अंतिम सूची में जगह नहीं बना सकी। सिंह ने कहा कि झांकी का चयन मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होता है।पश्चिम बंगाल की झांकी भी केंद्र से खारिज
गौरतलब है कि, केंद्र ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल की झांकी को भी खारिज कर दिया है। जिसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। इससे पहले रविवार को, ममता बनर्जी ने आने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल की प्रस्तावित झांकी की अस्वीकृति पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और परेड में पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी को शामिल करने का अनुरोध किया।
गणतंत्र दिवस परेड में तमिलनाडु की झांकी नहीं शामिल होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नाराजगी जाहिर की है। सोमवार को पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु की झांकी परेड में शामिल नहीं होने से राज्य के लोगों की भावनाएं आहत होंगी

मुंबई डाकयार्ड में आईएनएस रणवीर में विस्फोट, भारतीय नौसेना के तीन सैनिक शहीद

नई दिल्ली,

मुंबई में नौसेना डाकयार्ड में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस रणवीर में मंगलवार को हुए विस्फोट में नौसेना के तीन जवान शहीद हो गए। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
मुंबई में वारशिप आईएनएस रणवीर में धमाका हुआ है।
इस धमाके में भारतीय नौसेना के तीन सैनिक शहीद हुए हैं।
ताजा अपडेट के मुताबिक धमाके के कारणों का जांच जारी है।
भारतीय नौसेना के अधिकारी ने कहा कि नेवल डाकयार्ड मुंबई पर आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।
भारतीय नौसेना के बयान में कहा गया है, मुंबई नेवल डाकयार्ड में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, आईएनएस रणवीर के एक आंतरिक कंपार्टमेंट में विस्फोट के कारण नौसेना के तीन सैनिकों की मौत हो गई।
जहाज के चालक दल ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है।
फिलहाल किसी बड़े नुकसान को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।बताया जा रहा है कि आईएनएस रणवीर नवंबर 2021 से पूर्वी नौसेना कमान से क्रास कोस्ट आपरेशनल तैनाती पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था।
इस घटना के कारणों की जांच के लिए एक बोर्ड आफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है।
मुंबई में वारशिप आईएनएस रणवीर में धमाका हुआ है।
इस धमाके में भारतीय नौसेना के तीन सैनिक शहीद हुए हैं।
ताजा अपडेट के मुताबिक धमाके के कारणों का जांच जारी है।
भारतीय नौसेना के अधिकारी ने कहा कि नेवल डाकयार्ड मुंबई पर आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।

चुनावी रण में भाजपा अपने तरकश का सबसे बड़ा तीर छोड़ने की तैयारी में

मेरठ।

चुनावी रण में भाजपा अपने तरकश का सबसे बड़ा तीर छोड़ने की तैयारी में है। पार्टी ने अपने सबसे बड़े योद्धा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मेरठ में एक बार फिर बड़ी रैली कराने की योजना बनाई है। कोविड प्रोटोकाल 23 जनवरी को हटा तो भाजपा दिग्गजों के जमावड़े से नया चुनावी माहौल बनाएगी। कोविड प्रोटोकाल से पहले दो जनवरी को पीएम नरेन्द्र मोदी की रैली सरधना में हुई थी, जिसमें सिर्फ मेरठ, मुजफ्फरनगर के ही चेहरे थे। 2017 विस चुनाव से पहले शताब्दीनगर में, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ में पश्चिम उप्र को साधने के लिए नरेन्द्र मोदी की बड़ी रैली की गई थी। भाजपा की दृष्टि से पश्चिम क्षेत्र में 14 जिलों की 71 विस सीटों को शामिल किया जाता है।स्टार प्रचारकों को बुलाने की रणनीति
पश्चिम की राजनीतिक प्रवृत्ति चुनावी समीकरण बदल देती है। इसे राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है। कोविड प्रोटोकाल में राजनीतिक रैलियों पर रोक है। भाजपा के पास स्टार प्रचारकों की बड़ी टीम है। भाजपा और सपा के बीच इंटरनेट मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। पहले चरण में दस फरवरी को मेरठ समेत पश्चिम की 67 सीटों पर चुनाव होगा। भाजपा समेत सभी दल डिजिटल प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार का पारा चढ़ नहीं पा रहा।कई योद्धाओं को बुलाने की तैयारी
पश्चिमी उप्र की राजधानी कहलाने वाले मेरठ में प्रचार के लिए पार्टी ने पीएम नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी को बुलाने की रणनीति बनाई है। क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर का कहना है कि पार्टी डिजिटल प्लेटफार्म पर सघन संपर्क अभियान चलाने के साथ शक्तिकेंद्रों पर बैठक भी करेगी। कोविड प्रोटोकाल हटते ही दिग्गजों की चुनावी रैलियां कराई जा सकती हैं।चुनावी पैमाने पर खास है पश्चिम उप्र उत्तर प्रदेश का चुनावी शंखनाद पश्चिम से होता है। किसान आंदोलन की धुरी रहने के साथ ही किसानों के ज्यादातर भावनात्मक मुद्दे यहीं से तय होते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों और कैराना पलायन पर भाजपा लगातार अखिलेश सरकार पर हमलावर है।

उम्मीदवारों की बात मतदाता तक कैसे पहुंचा रहे डिजिटल विशेषज्ञ

मुरादाबाद, विधानसभा चुनाव के प्रचार पर कोरोना की मार हावी है। इससे चुनाव आयोग ने भौतिक रूप से होने वाली रैलियों पर रोक लगाई है। इससे अब डिजिटल प्रचार प्रसार पर जोर है। इस विधान सभा चुनाव में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर काफी हलचल देखने को मिली है। चुनाव प्रचार होने से भौतिक रैलियां बंद होने से डिजिटल माध्यम एक अच्छा विकल्प बनकर उभर रहा है। क्योंकि, सोशल मीडिया के माध्यम से चुनावी पार्टियां और वोटरों को सीधे टारगेट करना आसान है।प्रत्याशी व इनके लिए काम

करने वाले फ्री हैंडलेस वर्कर तकनीकी सलाहकारों से राय लेने लगे हैं। सोशल मीडिया मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, कंटेंट रणनीतिकारों की भूमिका डिजिटल प्रचार से बढ़ गई है। चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया तकनीकी प्रोफेशनल विभिन्न प्लेटफार्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम , जीमेल, वॉट्सऐप मैसेज-ग्रुप्स, टेलीग्राम, सिग्नल एवं ट्विटर का प्रयोग प्रचार के लिए रैलियों पर रोक लगने से बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार के लिए उपरोक्त तकनीकी विशेषज्ञ बताते हैं कि वह उम्मीदवार का प्रचार उनके वोटरों तक पहुंच सके, उसकी प्लानिंग को अलग-अलग केटेगरी के हिसाब से बताते हैं। किस प्रकार के प्रचार का कौन-सा पोस्टर, वीडियो या कौन-सा कंटेंट दिखाना है, प्लान करके वोटर को डिजिटल के माध्यम से पहुंचाते हैं।

- कोरोना संक्रमण के कारण यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा रखी है।
ऐसे में अब राजनीतिक दलों का डिजिटल प्रचार पर जोर है।
इसके चलते इस विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर काफी हलचल देखने को मिल रही है।
विधानसभा चुनाव के प्रचार पर कोरोना की मार हावी है।

कांग्रेस भाजपा की उम्मीदों को देना चाहती है झटका

साल 2016 में बगावत का झटका झेल चुकी कांग्रेस भाजपा को उसी अंदाज में जवाब देने जा रही है। भाजपा सरकार में मंत्री रहे यशपाल आर्य और उनके पूर्व विधायक बेटे की वापसी के बाद अब पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को शामिल करने की तैयारी है। उनके साथ कांग्रेस की पृष्ठभूमि के कुछ विधायक भी भाजपा छोड़ सकते हैं। बागियों की घर वापसी के माध्यम से कांग्रेस की कोशिश है कि भाजपा की दोबारा प्रचंड बहुमत पाने की कोशिशों को झटका दिया जाए।पांच साल पहले कांग्रेस जिस बड़े असंतोष से गुजरकर बिखरने की हालत में पहुंच गई थी, उसे फिर से दोहराने की तैयारी प्रमुख विपक्षी पार्टी कर रही है।

ड्रैगन के एकदम समर्पी हवाई अमेरिका की महाविनशिक परमाणु पन्ब्बब्बी

नई दिल्ली, अमेरिका और चीन के बढ़ते तनाव के बीच एक बार फरि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य विवाद और गहरा गया है। दरअसल, अमेरिकी नौसेना के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक यूएसएस पनडुब्बी के गुआम द्वीप के एक दुर्लभ बंदरगाह पर अचानक आवक से यहां हलचल बढ़ गई है। इस पनडुब्बी की दस्तक से चीन और उत्तर कोरिया सकते में हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिका ने गुआम द्वीप पर अपनी पनडुब्बी क्यों भेजी इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जंग की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है अमेरिका के इस कदम से चीन और उत्तर कोरिया को क्यों एतराज है इस तमाम सवालों पर क्या है विशेषज्ञ की राय।

1- प्रो. हर्ष वी पंत का कहना है कि अमेरिकी नौसेना ने अपनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उतार कर उसने उत्तर कोरिया और चीन को सख्त संदेश दिया है। बाइडन प्रशासन के इस कदम से यह साफ है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल और हस्तक्षेप पर वह अपनी आंखें नहीं बंद कर सकता है। इसके साथ अमेरिकी प्रशासन ने यह भी संदेश दिया है कि वह अपने मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वह मित्र राष्ट्रों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। बता दें कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के दखल से जापान एवं अन्य देशों की चिंता बढ़ रही है।
2- अमेरिकी नौसेना ने सबसे शक्तिशाली पनडुब?बी को गुआम द्वीप पर उतार कर यह संकेत दिया है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अमेरिकी सेना जंग के लिए भी तैयार है। यह अमेरिकी प्रशासन को चीन की खुली धमकी का जवाब है। बाइडन प्रशासन ने यह दिखा दिया है कि चीन की किसी भी हरकत के जवाब के लिए उसकी नौसेना पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। उन्होंने कहा कि यह हम

हरक सिंह रावत को लेकर क्या बोल गए सीएम पुष्कर सिंह धामी

पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी तो होगी, लेकिन हनक गायब रहेगी। हरक के दांवपेच के जवाब में पार्टी से निष्कासन और मंत्री पद से बर्खास्त कर भाजपा ने जिस तरह आक्रामक तेवर अपनाए, उससे कांग्रेस में मनमुताबिक तरीके से उनकी वापसी की राह में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान की बागडोर संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनकी वापसी पर सामूहिक निर्णय लेने की बात कहकर हरक के लिए स्थिति सहज नहीं होने के संकेत दे दिए हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच माना जा रहाभाजपा ने एक से ज्यादा टिकटों को लेकर लंबे समय से दबाव बना रहे हरक सिंह रावत के लिए चुनाव के ऐन मौके पर स्थिति असहज बना दी है। इसका असर कांग्रेस में उनकी एंट्री पर भी साफतौर पर दिखाई दे रहा है। इस बारे में पार्टी ने अभी तक पत्ते तक नहीं खोले हैं। सोमवार को दिल्ली में मौजूद हरक सिंह रावत इसी वजह से बेचैन दिखाई दिए। भावुक होकर उन्होंने अपने निष्कासन को लेकर भाजपा को कोसा। साथ में यह भी कहा कि टिकट मिले या न मिले, लेकिन भाजपा को हराने के लिए वह कसर नहीं छोड़ेंगे।कांग्रेस में बतौर हीरो वापसी की हरक की मंशा को उस वक्त और झटका लगा, जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पहले इस मामले की जानकारी होने से ही इन्कार कर दिया। 2016 में उनकी सरकार गिराने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट के लिए पहले खेद जताया जाना चाहिए। वापसी पर फैसला जन भावनाओं को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। रावत ने हरक के कांग्रेस में शामिल होने का सीधे तौर पर विरोध तो नहीं किया, लेकिन उनके इस रुख को नई उलझन के तौर पर देखा जा रहा है।हालांकि कांग्रेस हरक की वापसी को भाजपा पर प्रहार के मौके के रूप में भुनाना चाहती है।

तिरंगे के अपमान पर गंभीर हुई केंद्र सरकार

ध्वज संहिता के प्रति सरकारी निकायों व एजेंसियों में जागरूकता की कमी

नई दिल्ली,

केंद्र ने गणतंत्र दिवस से पहले सरकारी संगठनों, एजेंसियों और लोगों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने संबंधी नियमों एवं परंपराओं के बारे में जागरूकता के स्पष्ट अभाव को रेखांकित किया है और राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि तिरंगे का अपमान नहीं हो।
केंद्र ने गणतंत्र दिवस से पहले सरकारी संगठनों एजेंसियों और लोगों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने संबंधी नियमों एवं परंपराओं के बारे में जागरूकता के स्पष्ट अभाव को रेखांकित किया है और राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि तिरंगे का अपमान नहीं हो।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सुनिश्चित करने के लिए कहा
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे एक संवाद में कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि लोग सांस्कृतिक एवं खेल कार्यक्रमों में भाग लेते समय केवल कागज के झंडों का इस्तेमाल करें और इन झंडों को जमीन पर फेंकने के बजाय गरिमा के अनुरूप निजी तौर पर इनका निस्तारण किया जाए।भारत की ध्वज संहिता के अनुसार, आमजन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सामाजिक एवं खेल समारोहों में कागज का बना राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को दर्शाता है

और इसलिए इसका एक सम्मानजनक स्थान होता है।ध्वज के प्रति सम्मान के लिए जागरूकता अभियान चलाए राज्य ध्वज के प्रति सार्वभौमिक प्रेम एवं सम्मान तथा वफादारी होती है। मंत्रालय ने कहा कि इसके बावजूद राष्ट्रीय ध्वज को फहराने पर लागू होने वाले कानूनों एवं परंपराओं के संबंध में लोगों के साथ-साथ सरकार के संगठनों या एजेंसियों में अक्सर जागरूकता की स्पष्ट कमी देखी जाती है। गृह मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि वे इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाएं और इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के जरिए इसका व्यापक प्रचार करें। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और राष्ट्रीय ध्वज को फहराने संबंधी नियमों से जुड़ी एवं 2021 में संशोधित भारतीय ध्वज संहिता, 2002 की प्रति मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
केंद्र ने गणतंत्र दिवस से पहले सरकारी संगठनों एजेंसियों और लोगों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने संबंधी नियमों एवं परंपराओं के बारे में जागरूकता के स्पष्ट अभाव को रेखांकित किया है और राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि तिरंगे का अपमान नहीं हो।

- केंद्र ने गणतंत्र दिवस से पहले सरकारी संगठनों एजेंसियों और लोगों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने संबंधी नियमों एवं परंपराओं के बारे में जागरूकता के स्पष्ट अभाव को रेखांकित किया है और राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि तिरंगे का अपमान नहीं हो। केंद्र ने गणतंत्र दिवस से पहले सरकारी संगठनों, एजेंसियों और लोगों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने संबंधी नियमों एवं परंपराओं के बारे में जागरूकता के स्पष्ट अभाव को रेखांकित किया है

नई तकनीकों के बीच रोजगार की चुनौती

तमाम वैश्विक आकलनों के अनुसार भारत विश्व की सबसे तेज आर्थिक विकास हासिल करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। वैश्विक सलाहकारी संस्था प्राइस वाटरहॉउस कूपर्स ने कहा है कि 2050 में भारत चीन के बाद विश्व की नंबर-2 अर्थव्यवस्था बन सकता है, यदि आर्थिक सुधारों को लागू किया जाए। सामान्य रूप से वैश्विक संस्थाओं का दबाव रहता है कि जीएसटी, बुनियादी संरचना, पूंजी के मुक्त आवागमन और मुक्त व्यापार जैसे सुधारों को लागू किया जाए। गौर करने वाली बात यह है कि इन्हीं सुधारों को लागू करने के बावजूद हमारी आर्थिक विकास दर पिछले छह वर्षों में लगातार गिर रही है। इसलिए इतना सही है कि हमें आर्थिक नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन यह सही नहीं कि इन्हीं आर्थिक सुधारों के सहारे हम आगे बढ़ सकेंगे। यहां विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थ व्यवस्था और आर्थिक विकास दर में गिरावट के विपरीताभास से भ्रमित नहीं होना चाहिए, चूंकि हमारी कथित तेज विकास दर अंधों में काना राजा जैसी है। सत्य यह है कि हमारी आर्थिक विकास दर में गिरावट केवल आर्थिक नीतियों के बल पर नहीं संभल सकती है।

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती नई तकनीकों से सामंजस्य बैठाने की है। सेंट स्टीफेंस यूनिवर्सिटी कनाडा के प्रोफेसर मैथ्यू जानसन ने कहा है कि 2035 तक 50 प्रतिशत रोजगार का हनन हो जाएगा क्योंकि ये कार्य रोबोट द्वारा किए जाएंगे। भारत के लिए यह परिस्थिति विशेषकर दुरूह है क्योंकि बड़ी संख्या में युवा हमारे श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। यदि इन्हें आय अर्जित करने का समुचित अवसर नहीं मिलेगा तो ये कुंठित होंगे और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होंगे। औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के एक प्रोफेसर ने बताया कि उनके एमए की डिग्री हासिल किए हुए छात्र एटीएम तोड़ने जैसी आपराधिक घटनाओं में लिप्त हो रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं हैं। दूसरी तरफ केरल में एक रेस्तरां में एक रोबोट द्वारा भोजन परोसा जा रहा है और हमारी अपनी मेट्रो में भी बिना ड्राईवर की ट्रेन को चलाया गया है। इसलिए 2 परस्पर विरोधी चाल हमारे सामने है। एक तरफ नई तकनीकों के उपयोग से रोजगार का हनन हो रहा है तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में युवा श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इस समस्या को और गंभीर बनाया है हमारी उन नीतियों ने जिनमें छोटे उद्यमियों को बड़े उद्यमों से सीधे प्रतिस्पर्धा में खड़े होने के लिए कहा गया है। बड़े उद्योगों की उत्पादन लागत कम आती है। जैसे दवा का उत्पादन करने वाली बड़ी कम्पनी कच्चे माल को चीन से आयात करेगी, कंटेनर को ब्राजील से लाएगी और इलेक्ट्रानिक उपकरण जर्मनी से आयात करेगी। इनके पास अच्छी गुणवत्ता के इंजीनियर होंगे।

बड़े पैमाने पर भी उत्पादन करने से लागत कम आती है, जैसे घानी से तेल निकालने में लागत ज्यादा आती है जबकि एक्सपेलर में लागत कम आती है।

इसलिए बड़े उद्योगों को बढ़ावा देकर हम सस्ते माल का उत्पादन अवश्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें रोजगार का हनन हो रहा है। हमारे सामने ही नहीं बल्कि विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम युवाओं को इस बदलते तकनीकी परिदृश्य में रोजगार उपलब्ध कराएं। अंतरराष्ट्रीय सलाहकारी कम्पनी आर्थर डी लिटिल और बैंक आफ अमरीका ने कहा है कि स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन और छोटे उद्योगों को सहायता देनी चाहिए। लेकिन प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं होगा। कारण यह कि छोटे उद्यमी की उत्पादन लागत ज्यादा आएगी ही। इन्हें कच्चा माल छोटी मात्रा में स्थानीय सप्लायर से खरीदना पड़ता है, तुलना में घटिया गुणवत्ता के इलेक्ट्रानिक उपकरण लगाने पड़ते हैं और एक ही व्यक्ति को उत्पादन, बैंक, खाता, श्रमिक, आदि सब काम देखने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों में इनकी कुशलता बड़ी कम्पनियों की तुलना में न्यून होती है। इस समस्या का समाधान भारत सरकार द्वारा छोटे उद्योगों के क्लस्टर बनाकर हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मनमोहन सिंह सरकार के समय एक कमेटी ने कहा था कि छोटे उद्योगों का विशेष स्थानों पर एक झुण्ड बना दिया जाए जैसे मुरादाबाद में पीतल के सामान का और लुधियाना में हौजरी का, तो ये बड़े उद्योगों का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। इनके कई कार्य सामूहिक स्तर पर किए जा सकते हैं जैसे कच्चे माल की गुणवत्ता की टेस्टिंग करना अथवा प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण सामूहिक रूप से स्थापित करना इत्यादि। लेकिन इस नीति के बावजूद अपने देश में छोटे उद्योग पिट रहे हैं और रोजगार की समस्या गहराती जा रही है।

इसलिए केवल समर्थन की हवाई बातों को करने के स्थान पर हमें समझना होगा कि छोटे उद्योगों को यदि जीवित रखना है तो उन्हें वित्तीय सहायता देनी ही पड़ेगी। हमें यह स्वीकार करना होगा कि छोटे उद्योगों द्वारा बनाए गए माल की लागत अधिक होगी। जैसे बड़े उद्योग में बनाई गई टीशर्ट 200 रुपए में उपलब्ध हो सकती है तो छोटे उद्योग द्वारा 250 रुपए में। इस ऊंचे मूल्य को उपभोक्ताओं को वहन करना होगा। जो टीशर्ट हमें बड़ी कम्पनी से 200 रुपए में मिल सकती है उसे छोटे उद्योगों से उपभोक्ता को 250 रुपए में खरीदना होगा। प्रश्न है कि ऐसा क्यों किया जाए? मेरा मानना है कि हमें इस 50 रुपए के अतिरिक्त खर्च को 'रोजगार टैक्स' के रूप में देखना चाहिए। हमारे सामने दो रास्ते हैं। यदि हम बड़े उद्योगों से उत्पादन कराएंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे, बेरोजगारी भत्ता देना होगा और अपराध से भी आर्थिक विकास का ह्रास होगा। इन बेरोजगारी भत्ते और अपराध के नियंत्रण के मूल्य को यदि छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता के रूप में दे दिया जाए तो छोटे उद्योग चल निकलेंगे, उनके द्वारा रोजगार उत्पन्न होंगे और ये खर्च करने की सरकार को जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न यह भी है कि यदि हमारे देश में टीशर्ट के उत्पादन का मूल्य 250 रुपए है तो हम वैश्विक बाजार में निर्यात कैसे करेंगे? इसका उपाय है कि निर्यात विशेष के लिए बड़े उद्योगों द्वारा सस्ते उत्पादन की छूट दे दी जाए, लेकिन घरेलू बाजार के लिए छोटे उद्योगों से ही उत्पादन कराया जाए। ऐसा करने से हम वैश्विक बाजार के लिए रोबोट से उत्पादन कर सकते हैं और घरेलू बाजार में श्रम से उत्पादन कर सकते हैं और हम दोनों उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं।

नियमों के सरलीकरण की तरफ बढ़ता प्रदेश

आज के संदर्भ में ''व्यापार में सुगमता'' शब्द उद्यमियों के लिए बहुत अपरिचित नहीं है। वर्ष 2014-15 से चल रहे इन सुधारों की प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिसके फ्लस्वरूप प्रदेश पूरे देश में व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में ''17वीं पायदान'' से ''7वें'' स्थान पर खड़ा है। इसे पहाड़ी राज्यों में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले प्रदेश के रूप में चिन्हित किया गया है। कमोबेश आज उद्यमी इस बात को स्वीकार करता है कि ''सिंगल विण्डो पोर्टल'' के माध्यम से व्यापार से संबंधित सभी विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं ''ऑनलाईन'' हो गई हैं व एक तय समय में दी जा रही हैं। इससे उद्यमी की परियोजना लागत व परियोजना स्थापित करने के समय में काफी कमी आई है। ''व्यापार में सुगमता'' के साथ-साथ ''जीवन में भी सुगमता'' एक अहम पहलू है। ''एक देश-एक राशन कार्ड'', का ही उदाहरण लें तो आज 75 करोड़ लाभार्थी देश के किसी भी कोने में रहते हुए राशन प्राप्त कर सकते हैं। यह कुल राशन कार्ड धारकों का लगभग 94.3 प्रतिशत बनता है। ऐसे ही ड्राविंग लाइसेंस, मोटर व्हीकल लाइसेंस व उनका नवीनीकरण भी अब ऑनलाईन हो गया है। एक आम व्यक्ति को अब बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।

उसका समय और पैसा बच रहा है। परंतु केन्द्रीय व राज्य स्तर पर अभी भी ऐसे हजारों नियम, कानून व प्रक्रियाएं हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में या तो बहुत पेचीदा हैं या उनकी उपादेयता समाप्त हो गई है। फिर भी नियम व कानून के नाम पर उद्यमी अथवा एक आम नागरिक इन्हें ढोए जा रहा है। 'व्यापार में सुगमता' व 'जीवन में सुगमता' तभी आ सकती है, यदि इन नियम, कानून व प्रक्रियाओं को या तो कम किया जाए, समाप्त किया जाए या इनका सरलीकरण किया जाए। इसे ही नियामक अनुपालन भार (मिनिमाइज़िंग रेगुलेटरी कम्पलाइंस बर्डन) को कम करना कहते हैं। जुलाई 2021 से केन्द्र सरकार के कैबिनेट सचिव की देख-रेख में ''औद्योगिक संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग'' भारत सरकार की ओर से यह राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में 22 दिसंबर को दिल्ली के ''अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केन्द्र'' में वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता व कैबिनेट सचिव की उपस्थिति में सभी राज्यों के लिए नियामक अनुपालन भार कम करने संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें सभी हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया कि कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। आज लगभग 26,300 से अधिक नियम, कानून व प्रक्रियाओं को कम किया जा चुका है। यदि हिमाचल की बात की जाए तो 1600 से अधिक प्रक्रियाएं कम कर दी गई हैं। ''नियामक अनुपाल भार'' कम करने के अंतर्गत बहुत सी प्रक्रियाएं आती हैं जैसेः निरीक्षण प्रणाली का युक्तिकरण, लाइसेंस/ प्रमाण पत्र/अनुमतियों का स्वतः पुनः नवीनीकरण और नवीनीकरण की अवधि को बढ़ाना, अनावश्यक पाक्षिक/ मासिक/ त्रैमासिक/ अर्धवार्षिक व सालाना रिटर्नों को या तो समाप्त करना या उनका सरलीकरण कर उन्हें एक पेज का बनाना, अनावश्यक रजिस्टर व रिकॉर्ड रखने की बाध्यता समाप्त करना, सभी हस्तलिखित रिकॉर्ड, रजिस्टर व रिटर्नों का सरलीकरण कर उन्हें डिजिटाइज करना, बाबा आदम के जमाने के नियम व कानूनों की पहचान कर उन्हें समाप्त करना तथा नवीनतम तकनीक का प्रयोग कर ''सिंगल साइन ऑन'' और ऑनलाईन प्रक्रियाओं को अपनाना इत्यादि।

इसके अतिरिक्त ऐसे नियम व कानूनों की पहचान कर उन्हें समाप्त करना, जिनकी अवहेलना करने पर जेल की सजा तक का प्रावधान हो जैसेः चौक बाउंस होने पर जेल जाने तक की नौबत आ जाती है।

संपादकीय

स्मृति शेष : पंडित बृजमोहन मिश्र यानी बिरजू महाराज

पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने रविवार और सोमवार की दरमियानी रात दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बिरजू महाराज की पोती रागिनी ने बताया कि महाराज का एक महीने से इलाज चल रहा था। बीती रात करीब 12.15-12.30 बजे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका।

पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे। वे शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका-बिन्दादिन घराने के अग्रणी नर्तक थे। पंडित जी कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे जिसमें अन्य प्रमुख विभूतियों में इनके दो चाचा व ताऊ, शंभु महाराज एवं लच्छू महाराज तथा इनके पिता एवं गुरु अच्छन महाराज भी आते हैं। हालांकि इनका प्रथम जुड़ाव नृत्य से ही है, फिर भी इनकी गायन पर भी अच्छी पकड़ थी तथा ये एक अच्छे शास्त्रीय गायक भी थे।

पंडित बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में नये आयाम जोड़े, नृत्य-नाटिकाओं को जोड़कर उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कथक को समर्पित 'कलाश्रम' की स्थापना भी की। इसके अलावा विश्व भ्रमण कर सहस्त्रों नृत्य कार्यक्रम करने के साथ-साथ कथक शिक्षार्थियों हेतु सैंकड़ों कार्यशालाएं भी आयोजित की। अपने चाचा शम्भू महाराज के साथ नई दिल्ली स्थित भारतीय कला केन्द्र, जिसे बाद में कथक केन्द्र कहा जाने लगा, उसमें काम करने के बाद इस केन्द्र के अध्यक्ष पर भी कई वर्षों तक आसीन रहे। तत्पश्चात 1998 में वहां से सेवानिवृत्त होने पर अपना नृत्य विद्यालय कलाश्रम भी दिल्ली में ही खोला।

बिरजू महाराज का जन्म कथक नृत्य के लिये प्रसिद्ध जगन्नाथ महाराज के घर हुआ था, जिन्हें लखनऊ घराने के अच्छन महाराज कहा जाता था। ये रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे। इनका नाम पहले दुखहरण रखा गया था, क्योंकि ये जिस अस्पताल पैदा हुए थे, उस दिन वहाँ उनके अलावा बाकी सब कन्याओं का ही जन्म हुआ था, जिस कारण उनका नाम बृजमोहन रख दिया गया। यही नाम आगे चलकर बिगड़ कर 'बिरजू' और उससे 'बिरजू महाराज' हो गया। इनको उनके चाचाओं लच्छू महाराज एवं शंभु महाराज से प्रशिक्षण मिला तथा अपने जीवन का प्रथम गायन इन्होंने सात वर्ष की आयु में किया। 20 मई, 1947 को जब ये मात्र 9 वर्ष के ही थे, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। कुछ वर्ष उपरान्त इनका परिवार दिल्ली में रहने लगा। बिरजू महाराज ने मात्र 13 वर्ष की आयु में ही नई दिल्ली के संगीत भारती में नृत्य की शिक्षा देना आरम्भ कर दिया था।

मेजर एचपीएस अहलूवालियाः महान पर्वतारोही और दिव्यांगों के मित्र को याद रखें

महान पर्वतारोही मेजर एचपीएस अहलूवालिया देश के 60 की उम्र पार कर गई पीढ़ी के लिए किसी नायक से कम नहीं थे। मेजर एचपीएस अहलूवालिया उस पर्वतारोही दल के सदस्य थे जिसने 20 मई 1965 को माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया था।

वह भारतीय सेना का पर्वतारोही दल था। यानी मेजर एचपीएस अहलूवालिया एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। मतलब तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी के छह सालों के बाद भारतीय दल एवरेस्ट पर चढ़ा था। मेजर अहलूवालिया ने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भी सक्रिय रूप से भाग भी लिया था। उन्होंने रणभूमि में दुश्मन सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। उनका विगत शुक्रवार को निधन हो गया। वे 85 साल के थे।

पाकिस्तान से जंग के दौरान उनके शरीर का एक हिस्सा पक्षाघात से ग्रस्त हो गया था। इससे वे विचलित नहीं हुए। वे आजीवन दिव्यांगजनों के हितों के लिए काम करते रहे। उन्होंने राजधानी में इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना की। यह देश का अपनी तरह सबसे शानदार अस्पताल है। इस अस्पताल में रीढ़ की बीमारियों से संबंधित रोगों का इलाज होता है। अब आप खुद देख लें कि कोई इंसान एक जीवन में कितने सार्थक काम कर सकता है।

मेजर अहलूवालिया का जीवन बेहद प्रेरक रहा। वे सैनिक, पर्वतारोही, लेखक और अस्पताल के संस्थापक थे। उनकी बात करते हुए हमें अपने देश के दिव्यांग जनों के हितों के बारे में संवेदनहीनता की मानसिकता को छोड़ना होगा। दिव्यांगजनों को भी बाकी नागरिकों की तरह ही देखा जाना चाहिए। उन्हें अहसान की जरूरत नहीं। भारत में मानसिक और शारीरिक तौर पर विकलांग लोगों को रोजाना किसी न किसी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। क्या हमारे देश के विकलांगों के मनमाफिक घरों या कमर्शियल इमारतों का निर्माण हो रहा है? इस सवाल का जवाब नकारात्मक ही मिलेगा। कारण यह है कि हमारे यहाँ दिव्यांग जनों के हितों को लेकर सरकार से लेकर समाज का रवैया ठंडा ही रहता है।

मेजर एचपीएस अहलूवालिया जैसे जागरूक नागरिक तो गिनती के हैं जो सरकार और समाज को जगाते रहते हैं। उन्हें बताते रहते हैं कि दिव्यांगजनों को उनकी हालत पर छोड़ा नहीं जा सकता। देश में 16 किस्म की विकलांगता है। मेजर अहलूवालिया स्वयं भी व्हीलचेयर पर चलते थे। वे मानते थे कि व्हीलचेयर पर चलने वाली आबादी

को अपने घर से बाहर लाने, कॉलेज या दफ्तर जाने के लिए बस पकड़ने, शापिंग कांप्लेक्स जाने या अन्य सार्वजनिक इमारतों में प्रवेश की वैसी ही सुविधा होनी चाहिए जैसी सामान्य लोगों के लिए होती है। लेकिन, स्थिति यह है कि अधिकतर स्थानों पर दिव्यांग व्यक्ति आसानी से आ-जा नहीं सकता। हमारे यहां इनके लिए हाई-राइज बिल्डिंगों और घरों में पर्याप्त जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर गंभीरता से नहीं सोचा जा रहा। यही स्थिति बुजुर्गों की भी है। हमारे देश में बुजुर्गों और विकलांगों दोनों की अनदेखी हो रही है। अब कुछ दिनों के बाद केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केन्द्रीय बजट पेश करेंगी। अगर वो अपने बजट प्रस्तावों में उन बिल्डरों को टैक्स में राहत दें जो दिव्यांग जनों को किसी तरह से मदद दे रहे हैं, तो यह एक तरह से मेजर एचपीएस अहलूवालिया जैसे विकलांगों और विकलांग सेवियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत में रीयल एस्टेट सेक्टर ने बीते चंद दशकों के दौरान लंबी छलांग लगाई है, पर उन रीयल एस्टेट कंपनियों को उंगलियों पर गिना जा सकता है जो विकलांगों तथा बुजुर्गों की सुविधा का ध्यान रखकर ही अपने प्रोजेक्टों का निर्माण कर रही हैं। अब भी आपको इस तरह की आवासीय और कमर्शियल इमारतें कम ही मिलेंगी जिनमें विकलांगों की व्हीलचेयर को लिफ्ट के अंदर लेकर जाया जा सकता है। लिफ्ट में इतना कम स्पेस रहता है कि व्हीलचेयर को उसके अंदर लेकर जाना मुमकिन ही नहीं होता। बाथरूम और किचन में कैबिनेट इतनी ऊंचाई में होते हैं कि विकलांग इंसान के लिए उनका इस्तेमाल करना बेहद कठिन होता है।

मेजर एचपीएस अहलूवालिया के बहाने यह भी कहना पड़ रहा है कि हमें अपने यहां पर्वतारोहियों को भी गति देनी होगी। उन पर्वातारोहियों को उनका हक देना होगा जिनकी खास उलब्धियां रही हैं। जिन दो पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट को पहली बार 29 मई 1953 को फतह किया था उनके नाम पर राजधानी में सड़कों के नाम हैं। सर एडमंड हिलेरी के नाम पर दिल्ली के चाण्क्यपुरी एरिया में सड़क है। वे 1985-1989 के बीच न्यूजीलैंड के भारत में हाई कमिश्नर थे। एडमंड हिलेरी के दफ्तर के दरवाजे पर्वतारोहियों, खिलाड़ियों, लेखकों वगैरह के लिए हमेशा खुले रहते थे। वे बेहद लोकप्रिय डिप्लोमेट थे। चाणक्यपुरी में ही तेनजिंह नोर्गे मार्ग भी है। उम्मीद की जाये कि अब राजधानी के किसी भाग में हम मेजर अहलूवालिया के नाम पर कोई सड़क या संस्थान को देखेंगे।

सब जानते हैं कि बछेन्द्री पाल एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थीं। उससे प्रभावित होकर हरियाणा की बेटी अनीता कुंडू ने भी माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। वह तिरंगे को तीन बार एवरेस्ट की चोटी पर और सातों महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों पर भी लहरा चुकी है। अनीता के गृह राज्य के हरियाणा से भारतीय दंपति विकास कौशिक और उनकी पत्नी सुषमा कौशिक एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे युवा दंपति बन चुके हैं। 45 साल की उम्र में प्रेमलता अग्रवाल ने सबसे उम्रदराज एवरेस्ट पर्वतारोही का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने भी कौशिक दंपति के साथ ही एवरेस्ट की चोटी को फतह किया था।

एक बात समझ लें कि पर्वतारोहण को गति तब ही मिलेगी जब इन पर्वतारोहियों की यात्राओं का खर्च सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र भी मिलकर वहन करे। पर्वतारोहण में बहुत पैसे खर्च होते हैं। ध्यान रहे कि भारत में 1960 से 1990 के दशकों तक सेना के पर्वतारोहियों के दल माउंट एवरेस्ट या दूसरी चोटियों को फतह करने के लिए निकलते थे।

चिंतनीय है लोकपाल के पास बैंकों के खिलाफ बढ़ती शिकायतें

यह बेहद चिंतनीय है कि केवल एक साल में बैंकिंग लोकपाल के पास बैंकों के खिलाफ 3 लाख 41 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश शिकायतें शहरी क्षेत्र से है तो क्रेडिट कार्ड और रिकवरी एजेंटों के दुर्व्यवहार को लेकर अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

विचारणीय यह भी है कि शिकायतों का सिलसिला निजी क्षेत्र के बैंकों का अधिक है। इस मामले में राहत की बात यह है कि सरकारी क्षेत्र या यों कहें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शिकायतें तुलनात्मक रूप से कम हैं। हालांकि एसबीआई में अन्य बैंकों के मर्जर के बाद हालात तेजी से बदले हैं और अब एसबीआई बैंक कर्मियों के व्यवहार को लेकर भी लोगों की सोच में बदलाव आया है और यह माना जा रहा है कि एसबीआई कर्मियों का व्यवहार भी रुखा होने लगा है।

चौंकाने वाली बात यह है कि ताजा आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं। कानपुर, दिल्ली, पटना, रायपुर और रांची एक-दूसरे के पीछे ही चल रहे हैं। मेट्रो सिटीज में सबसे अधिक 97 फीसदी शिकायतें क्रेडिट कार्ड से जुड़ी होने के साथ ही 80 प्रतिशत से ज्यादा शिकायतें रिकवरी एजेंटों की है। एक बदलाव और देखने को मिला है कि अब लोग ई मेल के साथ ही ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने में भी आगे आए हैं। यह सब तस्वीर आरबीआई लोकपाल कार्यालय के 2020-21 के जारी आंकड़ों के अनुसार है। यह तय माना जाना चाहिए कि 2021-22 में भी हालात लगभग वही है और कोई खास बदलाव नहीं दिखता है। सबसे गंभीर यह कि बैंकों द्वारा बिना किसी सूचना के चार्जेज के नाम से सीधे खातों से रकम काट ली जाती है। अब हालात यह हो गए हैं कि आए दिन किसी ना किसी नाम से खातों से चार्जेंज के नाम पर कटौती होने लगी है।

पिछले सालों में खासतौर से डीबीटी सिस्टम चालू होने और जनधन खातों के बाद बैंकों की पहुंच आम आदमी तक आसान हुई है। कोरोना काल ने लोगों को और अधिक ऑनलाइन पेमेंट व पेटीएम आदि एप्स के माध्यम से भुगतान को बढ़ावा मिला है। हालांकि साइबर ठगों ने इन साधनों से लोगों के खातों में सेंधमारी भी तेजी से शुरू कर दी है। कभी किसी नाम से तो कभी किसी और तरीके से बैंक खातों में साइबर ठगी के मामले दिन-प्रतिदिन आने लगे हैं तो इस तरह के समाचार भी समाचार पत्रों के

स्थाई कॉलम की तरह आने लगे हैं। आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है कि लिंक या किसी और बहाने से ओटीपी प्राप्त कर खातों से पैसे निकाल कर ठगी होने लगी है। हालांकि बैंकों ने इन मामलों में सतर्कता अभियान चलाकर लोगों को सचेत किया है पर परिणाम वही ढाक के तीन पात वाले ही हैं।

एक ओर जब से बैंकों से आसानी से ऋण मिलने लगे हैं तो लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी होने लगी है। कोई मकान के लिए तो कोई कार, व्हीकल, एलईडी या अन्य साधनों के लिए ऋण लेने लगे हैं। कोरोना के कारण लोगों की नौकरी प्रभावित हुई है तो वेतन भत्तों में कटौती के कारण आय प्रभावित हुई है। इससे ऋण की किस्त भी समय पर जमा नहीं होने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं बैंकों द्वारा जो रिकवरी एजेंट नियुक्त किए गए हैं उनका व्यवहार बेहद चिंताजनक होता जा रहा है। ऐन केन प्रकारेण वसूली के लिए डराने-धमकाने से लेकर कार आदि बीच रास्ते उठा ले जाना आम होता जा रहा है। बैंकों की तुलना में इस तरह की घटनाएं ज्यादातर वित्तदायी संस्थाओं द्वारा अधिक हो रहा है। पर है यह बेहद चिंतनीय। एक और यह कि पर्सनल लोन की सहज सुलभता भी लोगों को कर्जे के बोझ के नीचे दबाती जा रही है। कहने को तो रुपए पैसे की जरूरत तत्काल पूरी हो जाती है पर एक तो इसकी ब्याज दर और फिर किस्त समय पर नहीं चुकी तो दण्डनीय ब्याज दर पुराने जमाने के किसी साहूकार से कम नहीं है। ऐसे में एक बार इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है।

एक समय था जब बैक की नौकरी सफेदपोश व प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती थी तो बैंक कर्मियों का व्यवहार अनुकरणीय माना जाता था। मामूली शिकायत पर तत्काल कार्यवाही होती थी तो एक सीट से दूसरी सीट पर बदलाव होता रहता था। इससे बैंक स्तर पर किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं के बराबर होती थी। आज तो आए दिन बैंक कर्मियों द्वारा भी गबन घोटालों की खबर आम होती जा रही है। ऐसे गिने-चुने कर्मचारी ही हैं पर व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह तो उभर ही रहे हैं। समस्या की एक जड़ बैंकिंग क्षेत्र की कॉल सेंटर्स भी है। जब चाहे तब फोन करने में इन्हें महारत हासिल होने के साथ ही लुभावने वादों में लेकर लोगों को साध लेते हैं।

भले ही आज एक साल में 3 लाख 41 हजार शिकायतें बैंकिंग लोकपाल के पास दर्ज होना कम लग रही हो पर यह अपने आप में चेताने के लिए काफी है। बैंकों को भी अपनी व्यवस्था को सुधारना होगा। एक और बैंकों को पब्लिक और कस्टमर फ्रैण्डली बनना होता तो दूसरी और साइबर अपराध जैसे सेंध लगाने के तरीकों की तोड़ खोजनी होगी। बैंकों को अपनी प्रतिष्ठा स्वयं बनानी होगी तो पब्लिक ग्रिवेंस के प्रति संवेदनशील होना होगा।

लेख

इस्लाम नगर निवासी कर रहे पुनः सर्वेक्षण का बरसों से इंतजार

डेमोक्रैटिक फ्रंट
अशोक वर्मा पंचकूला *इस्लामनगर पिंजौर के निवासी अपने मकानों और प्लाटों के सर्वे के लिए हुडा /हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को बार बार लिख रहे हैं , परंतु विभाग है कि कानून और विद्या बैठा है दीपक एनर्जी इस्लाम नगर के निवासी सूरज किसी भाग को मुझे पिछले कई वर्षों से लिख रहे हैं कि उनकी और अन्य निवासियों की जमीन का पुनः सर्वेक्षण किया जाए परंतु संबंधित अधिकारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं सूरज शर्मा ने इस संवाददाता को बताया कि कार्य के अनुसार उनकी जमीन सरकारी रिकॉर्ड में अधिकृत है लेकिन उन्हें इसका कोई मुआवजा नहीं मिला रजिस्ट्री और कोटा की ओर से दिया गया एनओसी लेकिन मैं इस जमीन को किसी को बेच नहीं सकते इसका कारण यह है कि विभाग द्वारा लिए गए निर्णय से निवासियों को स्पष्ट रूप से अवगत नहीं कराया गया है कोई मौका मिला इसी अनिश्चितता के चलते हिंदुओं को इसका खामियाजा कितना पड़ता है 17 में इसी तरह की एक कार्यवाही के दौरान हुड्डा के नायब तहसीलदार बचन सिंह, पटवारी राकेश सैनी, कनिष्ठ अभियंता जे ई राजवीर सिंह द्वारा उषा मुद्गल का मकान नंबर 24 वार्ड नंबर 5 को तोड़ दिया गया इससे पूर्व उन्हें कोई नोटिस भी नहीं इसमें ध्यान देने योग्य बात है आसपास मकान नंबर 23 और 25 पर कोई कार्यवाही नहीं की गई आपको बता दें यहां गुड्डा के एक अन्य जी का मकान भी है जो तथाकथित सरकार द्वारा अधिकृत जमीन पर बना है कानूनन बाकी गैर कानूनी ही हैं यह कार्रवाई उन्होंने उस समय की जबकि परिवार शहर से बाहर था लौटने के बाद जमीन की मालकिन उषा शिकायत की साथी कालका तहसील में हुई जिसमें जारी एनओसी भी पेश किया जिसे कार्रवाई करने वाले कर्मचारियों ने बोगस बताया ।*

सूरज शर्मा ने बताया की शिकायत करने पर खुदा ने बताया कि मामले की कमेटी गठित कर दी गई है लेकिन जब कमेटी की रिपोर्ट जानने के लिए आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी मांगी गई तो उन्हें बताया गया कि इस मामले में कोई भी कमेटी गठित नहीं की गई।

अब सवाल यह उठता है कि उदय कर्मचारियों की माने तो संबंधित संपत्ति की रजिस्ट्री और एनओसी बोगस है जबकि मकान मालिक कालका तहसील से कोई रजिस्ट्री और हुड्डा द्वारा जारी एनओसी प्रमाण प्रमाण के रूप में पेश कर चुका है इस पर गुड्डा मस्ती करें प्राप्त नहीं हुआ इस बाबत आपके लिए महानिदेशक मुख्यमंत्री को भी शिकायत दी गई कि नाजायज तोड़फोड़ करने वाले कर्मियों कानूनी कार्रवाई की जाए संपत्ति की रजिस्ट्री और एनओसी की भी जांच पिंजौर थाने के एसीपी रमेश गुलिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा की यह मामला हुड्डा और शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र का है इस पर कार्रवाई नहीं बनती।

इसके पश्चात इस इलाके के अन्य मकानों और फोटो गीत स्थिति स्पष्ट करने के लिए सूरज शर्मा ने आरटीआई मांगी लेकिन उन्हें लगभग ढाई साल बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया मुख्य आयुक्त राज्य सूचना आयोग मे शिकायत के बाद आयोग द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना प्रदान न करने की एवज में अधिकारी आर के कटारिया को एक बार 12000 दूसरी बात 25000 भतार जुर्माना अदा करने के लिए अभी तक नाही संबंधित अधिकारी ने ना जुर्माने की राशि भरी ना ही सूचना प्रदान की।

सुरेश शर्मा का कहना है सेक्टर 3 4 5 की रजिस्ट्री आदि विभाग स्पष्ट रूप से सामने नहीं आएगा तो धांधली चलती रहेगी लोक अपनी ही जमीन पर नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें नहीं पता कब अधिकारी या कर्मचारी आकर उनके द्वारा किए गए निर्माण को अवैध घोषित कर दें और वह अपने ही घर से बेघर हो जाएं उनका कहना है के उन विभाग से बार-बार की गई अपील का कोई असर नहीं रहा अब पानी ऊपर बह गया है जल्दी से जल्दी अगर कार्यवाही नहीं होती के निवासियों के पास सरकार के खिलाफ आंदोलन करने कोई चारा ना होगा।

पंचकूला नगर निगम द्वारा सड़कों के किनारे घास लगाने हेतु लगे थे लाखों के टेंडर 1 साल बाद भी घास नजर नहीं आ रही- प्रशासन बेखबर

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के अधीन पंचकूला नगर निगम होने के बावजूद भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है प्रशासन के नाको तले सरेआम धड़ल्ले के साथ सरकार के सभी नियम कायदों को ताक में रखकर स्वयं नगर निगम के अधिकारियों की देखरेख में शहर के बीचो बीच सेक्टरों की मुख्य सड़कों के दोनों तरफ बर्मो पर घास लगाने हेतु लाखों का टेंडर लगाया गया था लेकिन इक्का-दुक्का जगहों पर घास नजर आ रही है ।

अशोक वर्मा
डेमोक्रैटिक फ्रंट
हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के अधीन पंचकूला नगर निगम होने के बावजूद भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है प्रशासन के नाको तले सरेआम धड़ल्ले के साथ सरकार के सभी नियम कायदों को ताक में रखकर स्वयं नगर निगम के अधिकारियों की देखरेख में शहर के बीचो बीच सेक्टरों की मुख्य सड़कों के दोनों तरफ बर्मो पर घास लगाने हेतु लाखों का टेंडर लगाया गया था लेकिन इक्का-दुक्का जगहों पर घास नजर आ रही है । बाकी जगह पर घास नजर नहीं आ रही बल के उन जगहों पर लगे बड़े-बड़े कूड़े के ढेरों ने पंचकूला की सुंदरता पर ग्रहण लगा दिया है । साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। स्वच्छता अभियान की सरेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रहे हैं निगम के अधिकारियों द्वारा घास के टेंडर लगाए जाने के बाद उनमें सिर्फ व सिर्फ खानापूर्ति की यह कवायद शहर के अधिकांश जनों को जरा भी रास नहीं आ रही है। उन्होंने इसे दोयम दर्जे का करतूत बता रहे हैं जानकारी के मुताबिक नगर निगम पंचकूला के कार्यकारी अभियंता के द्वारा शहर की मुख्य सड़कों की बर्मो प 'घास लगाने हेतु चार ठेकेदारों को लगभग 7000000 रुपए की राशि का टेंडर लगाया था अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते ठेकेदारों को सरकारी मशीन पानी के टैंकर और मलवा उठाने हेतु लाखों रुपए की कोटेशन ए भी लगाई गई लेकिन टेंडर लेने वाले ठेकेदारों के द्वारा अपनाए गए हद कंडोने सबको चौंका कर रख दिया है सेक्टरों की सड़कों पर घास नजर नहीं आ रही है साथ ही विभाग के संबंधित अधिकारियों ने उनके किए गए कार्यों को नजरअंदाज करके उनका भुगतान भी कर दिया गया। लेकिन ठेकेदारों के टेंडर उनकी देखरेख व मेंटेनेंस हेतु 1 साल का समय भी दिया लेकिन विभाग के किसी भी अधिकारी ने इन ठेकेदारों के किए गए कार्यों को देखने की जहमत नहीं उठाई स्थानीय लोगों तथा शहर के नामी गिरामी संस्थाओं ने हरियाणा सरकार व प्रशासन से इस घोटाले की जांच कराने की मांग की है

स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत -आनंद मदाना ।

डेमोक्रैटिक फ्रंट

खेल एवं युवा कार्यक्रम झज्जर और भारत सरकार के तत्वाधान में 12 जनवरी से 19 जनवरी स्वामी विवेकानन्द के जन्म दिवस पर झज्जर जिले में युवा दिवस मनाया जा रहा है इसी कड़ी में आज लायंस युवा क्लब मदाना के सौजन्य से गांव मदाना में मनाया गया।लायंस युवा क्लब के प्रधान आनन्द मदाना ने बताया कि कार्यक्रम का आगाज वार्ड नंबर 17की पार्षद लक्ष्मी देवी के पति सवीन कुमार और अजय नारा ने दीप जलाकर किया। आनन्द मदाना ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानन्द युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत थे जैसे कि आज कल युवा नशे की तरफ ज्यादा रुझान है परन्तु स्वामी विवेकानन्द ने कभी भी मांस,मदिरा का सेवन नहीं किया तभी तो स्वामी विवेकानन्द जी छोटी सी उम्र ही विद्वान हो गए थे और पूरी दुनिया में विख्यात हो गए थे। अजय नारा ने संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर युवा स्वामी विवेकानन्द के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जरूर सफल होगे। आनन्द मदाना ने बताया कि युवाओं ने शान्ति दिवस,सेमिनार,प्रभात फेरी निकालकर युवा दिवस मनाया।इस कार्यक्रम में विकास कौशिक, हर्ष कौशिक,हिमानी,नवदीप,सचिन,ज ीतेश,साहिल,सागर, हिमांशु,अजय,सुनील,रक्षित,हर्ष,अ मरदीप,राहुल,योगेश,हितेश,सुरेश मास्टर,परवीन मास्टर,संदीप मास्टर,जसबीर,नेशी आदि ने सहयोग किया।

और भारत सरकार के तत्वाधान में 12 जनवरी से 19 जनवरी स्वामी विवेकानन्द के जन्म दिवस पर झज्जर जिले में युवा दिवस मनाया जा रहा है...

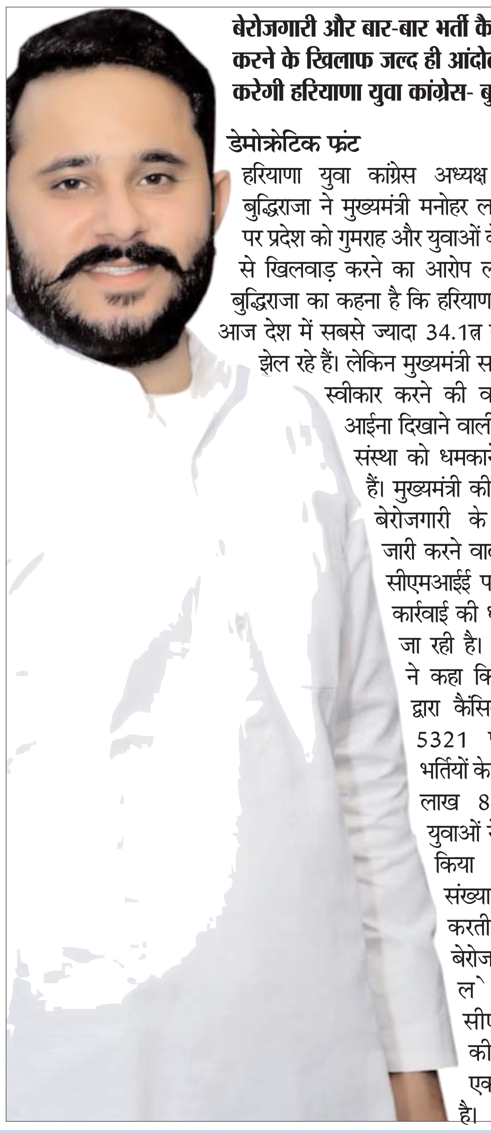

बेरोजगारी और बार-बार भर्ती कैंसिल करने के खिलाफ जल्द ही आंदोलन करेगी हरियाणा युवा कांग्रेस- बुद्धिराजा

डेमोक्रेटिक फ्रंट
हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर प्रदेश को गुमराह और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। बुद्धिराजा का कहना है कि हरियाणा के युवा आज देश में सबसे ज्यादा 34.1त्न बेरोजगारी झेल रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सच्चाई को स्वीकार करने की वजह उन्हें आईना दिखाने वाली संस्था को धमकाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने वाली संस्था सीएमआईई पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। बुद्धिराजा ने कहा कि सरकार द्वारा कैंसिल महज 5321 पदों की भर्तियों के लिए 26 लाख 88 हजार युवाओं ने अप्लाई किया था। यह संख्या साबित करती है कि बेरोजगारी को ल े क र सीएमआईई की रिपोर्ट एकदम सही है।

काल करे सो आज कर आज करे सो अब - डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़, बिना देरी किए प्रदेश के इच्छुक युवा 75 प्रतिशत लोकल रोजगार के लिए श्रम विभाग द्वारा जारी पोर्टल पर अपना आवेदन करें। कानून के मुताबिक हरियाणवी युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत रोजगार दिलाना मेरी जिम्मेदारी होगी। यह बात प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कही। वे सोमवार को साइबर चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से हजारों युवाओं के साथ रूबरू थे। इस दौरान उन्होंने युवाओं के साथ लाइव जुड़कर नए रोजगार कानून पर चर्चा की और उनके सुझाव लिए। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने रोजगार कानून लागू करने के लिए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार व्यक्त किया।

डिप्टी सीएम ने संत कबीर दास की ÷काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरि करेगा कब÷ पंक्तियां दोहराते हुए सभी युवाओं से सरकारी पोर्टल पर आवेदन करने का आह्वान किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रोजगार कानून से संबंधित विभाग द्वारा जारी पोर्टल पर अब तक करीब 1600 युवाओं ने आवेदन कर दिया है। इनमें सबसे ज्यादा हिसार जिले से 200 युवा शामिल है। इसी तरह अन्य जिलों जैसे जींद में 98, सोनीपत में 91, सिरसा में 42 आदि युवाओं ने आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निरंतर जिले अनुसार मॉनिटर कर रही है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे बिना देरी अपना आवेदन पोर्टल पर करें ताकि राज्य सरकार निजी क्षेत्र में उन्हें रोजगार देने की दिशा आगे बढ़े।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने वादे मुताबिक निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने के लिए यह कानून बनाया है और यह कानून सभी का सुझाव लेकर बनाया गया है। इस कानून के लागू होने से युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कम समय के सीजनल कार्यों में 75 प्रतिशत रोजगार कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि कानून में तीन माह के मॉनिटरिंग सिस्टम में यह फुलफिल नहीं है। इसी तरह दो वर्ष तक नई स्टार्टअप, नई आईटी कंपनियों को भी कानून में छूट दी गई है।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की एक घंटे की साइबर चौपाल में लगभग 1 लाख कमेंट आए, करीब 20 हजार लोगों ने लाइक किये और 10 हजार लोगों ने एक साथ लाइव देखा।

टीके के प्रमाणपत्र पर राज्यों में अलग-अलग है व्यवस्था, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश में किसी भी कार्य के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता नहीं है। हालांकि राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर इस संबंध में नियम बनाए हुए हैं।

वैक्सीन सर्टिफिकेट और कोविड निगेटिव रिपोर्ट को लेकर राज्यों की व्यवस्था पर एक नजर

दिल्ली राजधानी दिल्ली में सरकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों में स्टाफ के लिए टीके की कम से एक डोज अनिवार्य है। अन्य राज्यों से आने-जाने वालों के लिए टीके की कोई अनिवार्यता नहीं है।राजस्थान- राजस्थान में सरकारी कार्यालयों में स्टाफ के लिए टीका अनिवार्य है। निजी कार्यालयों को भी ऐसा करने को कहा गया है। अन्य राज्यों से आने वालों के लिए भी टीका अनिवार्य किया गया है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में किसी भी कार्य के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता नहीं है। राजधानी दिल्ली में सरकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों में स्टाफ के लिए टीके की कम से एक डोज अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़- राज्य में बाहर से आने वालों के लिए 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। टीका लगवा चुके लोगों के लिए भी यही नियम है। कार्यालयों में स्टाफ के लिए टीके की कोई अनिवार्यता नहीं है।झारखंड- सरकारी कार्यालयों में स्टाफ के लिए कम से कम एक टीका अनिवार्य है। स्कूल में अध्यापकों के लिए दोनों टीके अनिवार्य हैं। दूसरे राज्यों से आने वालों की आरटीपीसीआर जांच की जाती है।

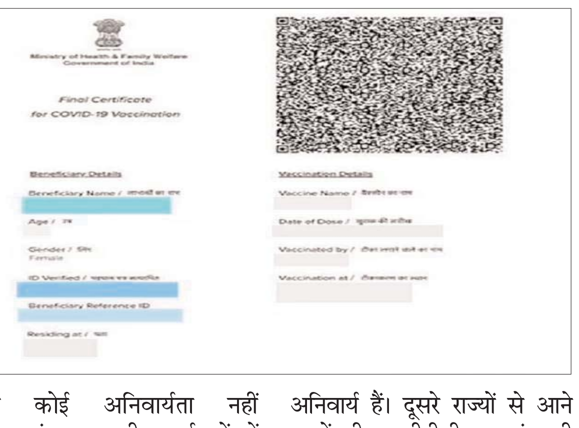

जम्मू-कश्मीर- बाहर से आने वालों के लिए निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जरूरी है। रिपोर्ट नहीं होने पर जांच की जाती है। सरकारी कार्यालयों में दोनों डोज अनिवार्य है।हरियाणा, बिहार- सरकारी कार्यालयों में दोनों डोज अनिवार्य हैं। जिन्होंने एक डोज लगवाई है, उन्हें यह बताना होगा कि दूसरी डोज का समय क्या है। बाजार, बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर अधिकारियों के मांगने पर टीके की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ सकता है।

बंगाल ट्रेन से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य नहीं है। एयरपोर्ट पर और सड़क मार्ग से आने वालों के लिए अंतरराज्यीय सीमा पर आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य है। लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है।

मध्य प्रदेश- मध्य प्रदेश में किसी आने-जाने वाले के लिए टीके की अनिवार्यता नहीं है। सीमावर्ती जिले बुरहानपुर के कलेक्टर ने महाराष्ट्र से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य की है।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब- टीके की कोई अनिवार्यता नहीं है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में किसी भी कार्य के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता नहीं है। राजधानी दिल्ली में सरकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों में स्टाफ के लिए टीके की कम से एक डोज अनिवार्य है।

दो आरोपियो को क्राईम ब्रांच नें अवैध शराब का धन्धा करनें के मामलें में दबौचा

डेमोक्रैटिक फ्रंट

पंचकूला
आरोपियो के पास अवैध शराब की 62 बोतलें बरामद करकें आरोपियो के खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्र में हरियाणा आबकारी अधिनियम 2020 के तहत मामला दर्ज किया गया।

क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पंचकूला की टीम नें अवैध शराब का धंधा करनें वालें आरोपी मोहन शाहू उर्फ बंजर माजरी चौंक के पीछे मीट मार्किट में देसी वा अग्रेजी शराब बेचने का धन्धा करतें हुए अवैध 24 पव्वे देसी शराब तथा 20 पव्वें अग्रजी शराब बरामद की और आरोपी विशाल सिंह वासी आशियाना सैक्टर 26 पंचकूला को अवैध शराब का धन्धा करनें के मामलें में सैक्टर 26 पंचकूला सें अवैध 36 हॉंफ देस्सी शराब बरामद करकें आरोपियो को गिरफ्तार किया गया ।

इसके अलावा आरोपी गुरमेल सिह पुत्र रचना राम को थाना चण्डीमन्दिर की टीम द्वारा और आरोपी अमरीक सिह पुत्र रुलदा सिह को थाना पिन्जौर की टीम अवैध शराब के मामलें में गिरफ्तार किया।

डीएम यशेन्द्र सिहं ने जिला में सुरक्षा के दृष्टिगत धारा 144 के आदेश किए जारी

डेमोक्रैटिक फ्रंट

जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रेवाड़ी में मनाए जाने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के दृष्टिगत अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। डीएम ने अपने आदेशों की स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत होटल, गेस्ट हाऊस, पीजी, धर्मशाला, मकान मालिक आदि को किराएदार, पेईंग गेस्ट व नौकर रखने से पूर्व उनकी आईडी व पूर्ण रिकार्ड मेनटेन करना होगा। जिला रेवाडी में कोई भी मकान मालिक किसी भी किराएदार या नौकर को बिना सत्यापन के अपने यहां न रखें ताकि जिले में बाहर से आकर रहने वाले लोगों की ठीक पहचान करके अपराधों पर अंकुश लगया जा सके।

डीएम ने निर्देश दिए कि बाहर से आकर ठहरने वाले व्यक्तियों से फार्म-सी भी भरवाएं। सभी होटल, गेस्ट हाऊस, पीजी, धर्मशाला, मकान मालिक आदि अपने यहां उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरें लगवाएं, जिनकी रिकार्डिंग क्षमता कम से कम 30 दिन की हो। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति संज्ञान में आता है तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन व पुलिस कंट्रोल रूम रेवाड़ी को दें।

ड्रोन उड़ाने व रखने पर लगाई पाबंदी

डीएम यशेन्द्र सिंह ने सुरक्षा के दृष्टिगत आईपीसी 1973 की धारा 144 के तहत जिला रेवाड़ी में से ड्रोन उड़ाने व रखने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि ड्रोनधारक अपने-अपने ड्रोन संबंधित थानों में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

असला धारक असला लेकर न घूमें

डीएम यशेन्द्र सिंह ने सभी असला धारकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे किसी भी सार्वजनिक समारोह व विवाह पार्टियों में असला लेकर न घूमें ताकि समारोह में शांति व्यवस्था बनी रहे और माहौल खराब न हों।

दुकानदार मोबाइल खरीदने व बेचने वाले का रखें पूरा रिकार्ड ः

डीएम ने निर्देश दिए कि सभी दुकानदार जो पुराने मोबाइल खरीदने व बेचने का कार्य करते हैं वे अपनी दुकान पर एक रजिस्टर लगाकर रखें तथा रजिस्टर में मोबाइल हैंडसेट व सिमकार्ड बेचने व खरीदने वाले व्यक्ति व लेन-देन का पूरा विवरण दर्ज करें।

इस बारे में शपथ पत्र भी प्राप्त करें कि बेचा जा रहा मोबाइल व सिमकार्ड चोरी का नहीं है, जिसमें बेचने वाले का पूरा नाम व अन्य विवरण अंकित किया जाए।

एसटीडी-पीसीओ संचालक कॉल्स का पूरा रिकार्ड करें मेनटेन

डीएम ने निर्देश दिए कि सभी एसटीडी व पीसीओ संचालक अपने बूथों पर आने-जाने वाली कॉल्स का पूरा रिकार्ड मेनटेन करके रखें।

- **जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रेवाड़ी में मनाए जाने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के दृष्टिगत अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।**
- **डीएम ने अपने आदेशों की स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।**
- **जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत होटल, गेस्ट हाऊस, पीजी, धर्मशाला, मकान मालिक आदि को किराएदार, पेईंग गेस्ट व नौकर रखने से पूर्व उनकी आईडी व पूर्ण रिकार्ड मेनटेन करना होगा।**

मंदिर में अवैध निर्माण को रुकवाने की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

- **शहर की अनाज मंडी में माल गोदाम रोड की तरफ बने राधा-कृष्ण मंदिर की जमीन पर कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह कहना है इनेलो महिला हलका अध्यक्ष प्रो. सीमा दलाल का।**
- **इनेलो नेत्री प्रो. सीमा दलाल, महिला मंडल की प्रधान कमला, सुनीता, कमलेश, सावित्री, संतोष, किरण व शकुंतला आदि ने बताया कि मंदिर की जमीन पर जयभगवान लोहिया, आशीष गर्ग, ऋषि कुमार पुन निर्माण के नाम पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे है, जो सही नहीं है।**

डेमोक्रैटिक फ्रंट

शहर की अनाज मंडी में माल गोदाम रोड की तरफ बने राधा-कृष्ण मंदिर की जमीन पर कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह कहना है इनेलो महिला हलका अध्यक्ष प्रो. सीमा दलाल का। इनेलो नेत्री प्रो. सीमा दलाल, महिला मंडल की प्रधान कमला, सुनीता, कमलेश, सावित्री, संतोष, किरण व शकुंतला आदि ने बताया कि मंदिर की जमीन पर जयभगवान लोहिया, आशीष गर्ग, ऋषि कुमार पुनः निर्माण के नाम पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे है, जो सही नहीं है। उन्होंने बताया कि अनाज मंडी माल गोदाम की तरफ लगभग 15 साल पहले महिला शक्ति ने अपने खर्चे व चंदा एकत्रित कर राधा कृष्ण मंदिर (शिवजी की प्रतिमा) के पास एक हॉल, बाथरूम व रसोई का निर्माण करवाया था। जब यह निर्माण कराया गया तो इन लोगों की ओर से काफी विवाद किया गया था।

उन्होंने बताया कि उस समय तत्कालीन विधायक नफे सिंह राठी ने मौके पर पहुंच कर इस हॉल का निर्माण कार्य करवाया था। इनेलो नेत्री सीमा ने बताया कि उक्त प्रभावशाली लोगों द्वारा मंदिर पर अवैध कब्जा करने की नीयत से फर्जी तरीके से पंचायती मंदिर समिति बनाकर मंदिर का पुनः निर्माण करवाने के नाम पर महिला मंडल द्वारा बनाई गई रसोई व बाथरूम तोड़ दिए गए हैं तथा हॉल के गेट के सामने दीवार खड़ी कर रहे है। जिसकी वजह से महिला मंडल की सैकड़ों महिला काफी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओ ने उक्त प्रभावशाली लोगों द्वारा मार्केट कमेटी की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा रुकवाने के लिए मार्केट कमेटी अधिकारी व उपमंडल अधिकारी को लिखित में शिकायत दर्ज करवाकर महिलाओं को न्याय दिलाने की मांग की है और सरकारी जमीन पर मंदिर का पुनः निर्माण के नाम पर जो प्रभावशाली लोग अवैध कब्जा कर रहे है, उस निर्माण को तुरंत प्रभाव से रुकवाए जाने की गुहार लगाई। महिलाओं का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ऐसे लोग भविष्य में इस प्रकार की हरकतें दोबारा न कर पाएं।

शहर की अनाज मंडी में माल गोदाम रोड की तरफ बने राधा-कृष्ण मंदिर की जमीन पर कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह कहना है इनेलो महिला हलका अध्यक्ष प्रो. सीमा दलाल का।

फकीर प्रधानमंत्री ही भारत को आगे ले जा सकता है

डेमोक्रैटिक फ्रंट

एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाने वाले क्या कहते हैं, यह बहुत मायने नहीं रखता लेकिन इसकी गंभीरता और इससे उत्पन्न संदेशों को कमतर भी नहीं आंका जा सकता। रही बात संदेशों की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश-दुनिया में इतने राजनीतिक संदेश दिए हैं कि अगर जनता उनका संस्मरण भर कर ले तो भी भाजपा को कोई चुनाव जीतने के लिए अतिरिक्त श्रम करने की जरूरत नहीं है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पड़ोसी देश में एक हाथी भिजवा दिया था। वह इसलिए कि वहां के बच्चों ने पत्र लिखकर शिकायत की थी कि उन्होंने हाथी नहीं देखा है और वे दुनिया भर के बच्चों के चाचा हो गए थे। कुछ लोग थोड़ा करके भी बहुत अधिक पा जाते हैं और कुछ लोग बहुत करके भी फकीर के फकीर ही रह जाते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। लाल किला की प्राचीर पर अपने संबोधन के बाद बच्चों से मिलते नरेंद्र मोदी को देखकर कौन नहीं कहेगा कि वे अपने देश के बच्चों से असीम प्यार करते हैं। आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में वे किस तरह देश के बच्चों की परीक्षा, स्वास्थ्य आदि की चिंता करते हैं, उसके अपने राजनीतिक संदेश हैं।

प्रयागराज कुम्भ में सफाईकर्मियों के पैर पखार कर उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि सफाईकर्मियों का लोकजीवन में कितना महत्व है। हमें स्वच्छ और स्वस्थ रखने में सफाईकर्मियों का बड़ा योगदान है। कभी महात्मा गांधी ने मल-जल की टोकरी अपने सिर पर रखी थी। नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मियों को सम्मान देने और दिलाने की उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम किया था।

याद करें, 4 दिसंबर, 2016 को मुरादाबाद में दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह संभाषण जिसमें उन्होंने कहा था कि देश से गरीबी हटाने के लिए यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का विकास जरूरी है। मैं यूपी से सांसद बनने के लिए नहीं लड़ा बल्कि गरीबी हटाने के लिए यहां से चुनाव लड़ा। न मेरा कोई नेताजी है, न हाईकमान है। मेरा जो कुछ है, आप ही लोग हैं। जनता ही मेरी हाईकमान है।हिंदुस्तान की पाई-पाई पर आप लोगों का हक है। विरोधी लोग ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या कर लेंगे? हम तो फकीर आदमी हैं। झोला लेकर चल पड़ेंगे।

ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों से लड़ने की ताकत दी है। यह और बात है कि चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव ने इस पर चुटकी ली थी कि ऐसे कैसे झोला लेकर चल देंगे, हम जाम तलाशी लेंगे की झोली में ले क्या जा रहे हो। इसमें शक नहीं कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने लालू की बातों में आनंदानुभूति प्राप्त की थी।

भगवान केदारनाथ की गुफा में जब इस देश ने फकीर स्वरूप नरेंद्र मोदी को रात भर साधना करते देखा तो लगा कि नहीं, वाकई कोई फकीर ही इस देश को आगे ले जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में यही हालत कमोबेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। मुख्यमंत्री निवास में बिना किसी एसी-कूलर के एक सामान्य से तखत पर शयन करने और उत्तर प्रदेश को तरक्की के शिखर पर ले जाने वाले योगी आदित्यनाथ को बाबा मुख्यमंत्री और चिलमजीवी कहने वाले नेताओं का क्या कहा जाए जिनकी आंखें इतना भी नहीं देख पा रहीं, वे प्रदेश का विकास करेंगी भी तो किस तरह। फकीर तो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी कहा गया लेकिन उनकी लगाई आरक्षण की आग देश को कितनी भारी पड़ी यह भी किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी राहुल गांधी, मणि शंकर अय्यर और शशि थरूर ने विगत 5-7 सात सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ नहीं कहा लेकिन मानना पड़ेगा मोदी को, उन्होंने इन नेताओं के आरोपों के कचरे से भी अपने लिए राजनीतिक संभावनाएं तलाश लीं और देश को प्रकारांतर से एक संदेश दिया कि बेकार कुछ भी नहीं होता।

गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन लिंक से होगा चयन डीसी

झज्जर। जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह में उन जिलावासियों को भी सम्मानित किया जाएगा। जिन्होंने अपने जिले को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया है। डीसी श्याम लाल पूनिया ने जिला के समग्र विकास में योगदान देने वाले जिलावासियों को स्वयं या अन्य को पुरस्कार के लिए नामित करने की अपील की। इस बार प्रशासन ने उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए जिलावासियों से सीधे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से एक लिंक भी जारी किया गया है। जिला के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनमें ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाकर सीटीजन अवार्ड्स के लिंक पर लॉग इन किया जा सकता है। पांच श्रेणियों में किए जा सकेंगे नामांकन

प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन ने पांच श्रेणियों नामतः मानवसेवा, वीरता, गुड सिटीजन, चेंजमेकर व पर्यावरणविद श्रेणी के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए जिला के अधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर डाले गए लिंक पर आवेदन किया जा सकता है। साथ ही अधिक जानकारी के लिए जिला प्रशासन के नंबर 01251-252002 पर भी संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी फीडबैक से मिलेगा सम्मान जिला प्रशासन ने जिलावासियों के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों के फीडबैक का विकल्प भी रखा है। प्रभावशाली कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का फीडबैक भी इस ऑनलाइन फार्म के माध्यम से दिया जा सकता है। जिला प्रशासन के पास आवेदन करने की अंतिम 20 जनवरी को 11 बजकर 59 मिनट तक किया जा सकता है।

मेवात का दौरा करेंगे पंचायतराज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली

डेमोक्रैटिक फ्रंट

नूह मेवात (शौकीन कोटला) हरियाणा प्रदेश के पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने चंडीगढ़ में मंगलवार को जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमन अहमद ने मुलाकात की। उन्होंने देवेंद्र सिंह बबली को गठबंधन सरकार में मंत्री बनने पर ना केवल बधाई दी बल्कि उनके अथक प्रयासों की सराहना भी की। बातचीत में फिरोजपुर झिरका से जेजेपी के वरिष्ठ नेता अमन अहमद ने कहा कि पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से मिलकर उन्हें मेवात आने का न्योता दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि

मार्च में वह मेवात का दौरा अवश्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री देवेंद्र बबली जमीन से जुड़े नेता है वह जनता के लिए लंबे वक्त से संघर्ष करते आ रहे हैं। यही कारण रहा है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उन पर विश्वास किया और उसी भरोसे की बदौलत भाई देवेंद्र सिंह बबली को मंत्री पद का इनाम मिला है।

चौधरी अमन अहमद ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मेवात ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए जोर शोर से तैयारियां की जाएंगी ताकि भविष्य में भाई दुष्यंत चौटाला को उपमुख्यमंत्री की बजाए मुख्यमंत्री बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में अभी दो महीने का वक्त और लग सकता है।

नशीली गोलियां का सप्लायर दो दिन की रिमांड पर

डेमोक्रैटिक फ्रंट

गढ़ी थाना पुलिस ने नशीली गोलियां सप्लायर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से अदालत ने आरोपित को दो दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। आरोपित उत्तराखंड से नशीली गोलियां लेकर नरवाना पहुंचा था और डिलीवरी देकर खिसक गया था। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।

सीआईए स्टाफ को गत 17 दिसंबर को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जाखल से गाड़ी में नशीली गोलियां तस्करी कर बेचने के लिए गांव लोन की तरफ आ रहे हैं। जिसके आधार पर पुलिस ने धमतान साहिब से गांव लोन की तरफ जाने वाले रास्ते पर नाकेबंदी कर कार सवार तीन लोगों को काबू कर उनके कब्जे से 17,500 नशीली गोलियां पकड़ी थी। जिनका वजन सात किलो 297 ग्राम पाया गया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान जाखल निवासी रजत, प्रिंस तथा विक्रम के रूप में हुई थी। पुलिस रिमांड के दौरान सामने आया था कि गणेशपुरी हरिद्वार उत्तराखंड निवासी विनय सप्लाई को देकर गया था। गढ़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विनय को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से अदालत ने आरोपित को दो दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपित उत्तराखंड से नशीली गोलियां लाकर यहां पर सप्लाई करता था। गढ़ी थाना के जांच अधिकारी रविंद्र ने बताया कि आरोपित ने ही नशीली दवाइयों को सप्लाई किया था। आरोपित उत्तराखंड में कहां से दवाई लाता था और कहां पर इसके तार जुड़े हुए हैं। जिसके बारे में पूछताछ की जाएगी।

दीप्ति दीप को मिलेगा साहित्य गौरव सम्मान

डेमोक्रैटिक फ्रंट

*कासगंज- दीप्ति दीप को मिलेगा साहित्य गौरव सम्मान**

जनपद कासगंज की कवयित्री एवम साहित्यकार दीप्ति दीप का नाम राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, उ. प्र. , की ओर से साहित्य गौरव सम्मान के लिए चयनित किया गया है। लेखिका एवं कवयित्री दीप्ति दीप ने अपनी रचना धर्मिता से बड़ी तेजी के साथ साहित्य जगत में अपना मुकाम हासिल किया है। दीप्ति दीप को मिलने वाले सम्मान के लिए

भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर अभय चौटाला

डेमोक्रैटिक फ्रंट

इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला आज भिवानी जिला के कस्बा तोशाम में इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मा. नरेन्द्र वर्मा के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। इस दौरान इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है।

उन्होंने कहा कि डाडम पहाड़ में खनन करने वाली कंपनी को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। नियमों को ताक पर रखकर माइनिंग की जा रही है। यहां के हादसे की सीबीआई या किसी जज से जांच होनी चाहिए।

दस हजार का इनामी पांचवां आरोपित गुजरात से गिरफ्तार

डेमोक्रैटिक फ्रंट

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की अंडरग्राउंड पाइप लाइन से तेल चोरी करने के मामले में सीआईए फतेहाबाद पुलिस ने पांचवें आरोपित रमेश चन्द निवासी मथूरिया, जिला मैनपुरी (उत्तरप्रदेश) को गुजरात से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।

पुलिस द्वारा इस आरोपित पर 10 हजार रुपये का इनाम रखा हुआ था। आरोपित को पुलिस ने अदालत में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।

पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भोरिया ने बताया कि इस बारे सदर फतेहाबाद पुलिस ने 29 अक्टूबर को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लि. में कार्यरत सुपरवाइजर राममूर्ति निवासी करन्डी की शिकायत पर केस दर्ज किया था।

निगम आयुक्त को भेंट किए बच्चों के लिए नोटबुक व अन्य सामान

डेमोक्रैटिक फ्रंट

***हिसार** समाजसेवी एवं हमारा प्यार संस्था के सदस्य सुशील खरींटा ने नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग को कैंप कार्यालय में जरूरतमंद बच्चों के लिए नोट बुक व अन्य स्टेशनरी का सामान भेंट किया। बुक बैंक के माध्यम से गरीब व जरूरतमंद बच्चों को यह स्टेशनरी मुहैया करवाई जाएगी।*

नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने मंगलवार को कहा कि बुक बैंक को शहरवासियों का प्यार निरंतर मिल रहा है। इसी प्यार का परिणाम है कि आज 12,000 के आसपास किताबें हमारी विभिन्न लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, जिनका लाभ जरूरतमंद बच्चे उठा रहे है। अब शहर के जागरूक लोग किताबों के साथ-साथ स्टेशनरी भी दे रहे है जो हर्ष की बात है। समाजसेवी सुशील खरींटा ने कहा कि नगर निगम प्रशासन गरीब व जरूरतमंद बच्चों का भविष्य सुधारने में अहम योगदान दे रहा है।

शहर के प्रत्येक नागरिक का फर्ज बनता है कि वह नगर निगम के बुक बैंक में सहयोग करें। आज गरीब जरूरतमंद बच्चों को लिए मैंने नोटबुक, पैंसिल, रबड़ आदि सटेशनरी का सामान निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग को भेंट किया है।

स्वामी मुद्रक प्रकाशन संपादक : कोरल ने इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 6 पंचकुला,हरियाणा से छपवा कर कार्यालय म407/16 पंचकुला 134108 हरियाणा से मुर्दित किया।

Website : www.demokraticfront.com, E-mail : democraticfront2021@gmail.com